



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68]

No. 68]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1998/चैत्र 6, 1920

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1998/CHAITRA 6, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1998

विषय : आइसोबुटाइल बेनजीन के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अन्तिम निष्कर्ष

6/2/96-ए डी डी.—वर्ष 1995 में तथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण और वसूली तथा क्षति-निर्धारण), नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. प्रक्रिया

1. निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

I. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया जाएगा) को चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे चीन पी आर अथवा संबद्ध देश कहा जाएगा) से आइसोबुटाइल बेनजीन जिसे आगे आई बी बी कहा जाएगा) के आयात पर पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा करने और उच्च में वृद्धि करने के लिए नियम 23 के अन्तर्गत मै. विनाली आरगेनिक्स लि. से लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ था।

II. प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 134 सीमा-शुल्क दिनांक 31 अगस्त, 1995 द्वारा लगाए गए निश्चित पाटनरोधी शुल्क और अधिसूचना सं. 14/50/93-टी पी डी/ए डी डी दिनांक 27 जुलाई 1995 द्वारा चीन पी आर मूल के अथवा वहां से निर्यातित आई बी बी के आयात पर संस्तुति निश्चित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा आरम्भ करने के लिए अधिसूचना सं. 6/2/96-ए डी डी दिनांक 31 मार्च, 1997 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

III. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/50/93-टी पी डी/ए डी डी दिनांक 27 जुलाई 1995 द्वारा जो जांच सम्पन्न हुई थी उसका "पूर्ववर्ती जांच" के रूप में उल्लेख किया गया है।

IV. प्राधिकारी ने सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के सीमा-शुल्क उप शीर्ष 2933.30 के अन्तर्गत वर्गीकृत चीन पी आर मूल के या वहां से निर्यात होने वाले आई बी बी के आयात से संबंधित पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में दि. 31 मार्च, 1997 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

V. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग संगठनों (जिनके ब्यौरे पूर्ववर्ती जांच में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे) को अग्रसारित की और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार अपने लिखित विचारों से अवगत कराने का मौका दिया गया।

878 GI/98

(1)

VI. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में आई बी बी के ज्ञात सभी आयातकों और उपभोक्ताओं को अग्रसारित की (जिनके ब्यौरे पूर्ववर्ती जांच में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे) और उन्हें पत्र जारी होने के चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का परामर्श दिया गया।

VII. समीक्षा अवधि समेत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में आई बी बी के आयात के ब्यौरे उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से अनुरोध किया गया था। परन्तु सी बी ई सी से कोई सूचना नहीं मिली।

VIII. प्राधिकारी ने नियम 7(4) के अनुसार संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, किन्तु किसी भी निर्यातकों ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं भेजा।

IX. नई दिल्ली स्थित चीन पी आर के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार समीक्षा शुरू करने के बारे में इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/निर्माताओं को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर देने के लिए परामर्श दें। निर्यातकों को भेजी गई पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति समेत ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची दूतावास को भी भेजी गई थी।

X. नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में आई बी बी के ज्ञात आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गई थी। किन्तु किसी भी आयातकर्ता ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं भेजा था।

XI. याचिकाकर्ता से क्षति की मात्रा से संबंधित जानकारी मांगी गयी थी, जो प्राप्ति भी हो गयी थी। जरूरी समझी गई सूचना का भी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया था।

XII. मै. हरदीलिया कैमिकल्स लि. (आई बी बी का अन्य उत्पादक) को भी जांच प्रारम्भ करने के बारे में सूचित किया गया था तथा उनसे अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हों, को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। यद्यपि कंपनी ने 31 मई, 1997 तक समय बढ़ाए जाने का अनुरोध दिया था, तथापि उक्त कंपनी से कोई सूचना/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

XIII. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्राधिकारी के समक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया था। प्राधिकारी ने 6 अक्टूबर, 1997 को सुनवाई की थी जिसमें याचिकाकर्ता तथा मै. हरदीलिया कैमिकल्स लि. उपस्थित हुए थे। सुनवाई में उपस्थित हुयी पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचार लिखित में पेश करें। इन पार्टियों को परामर्श दिया गया कि वे विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रतियां एकत्र करें और उनसे अपने खण्डन यदि कोई हो को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

XIV. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अग्रोपनीय रूपान्तरण को एक सरकारी फाइल के रूप में उपलब्ध किया और किसी हितबद्ध पार्टी के निरीक्षण के लिए इसे खुला रखा गया।

XV. उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्यों/आधारों का खुलासा सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को किया गया तथा उन पर प्राप्त विचारों पर भी इन निष्कर्षों में विधिपूर्वक विचार किया गया है।

XVI. जांच की कार्यवाही 1 अप्रैल, 1996 से शुरू होकर 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए की गई थी।

ख. याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए विचार

2. सिनाती ऑरगेनिक्स लि. ने निम्नलिखित अनुरोध किए :

(I) इन जांचों के उद्देश्य के लिए सामान्य मूल्य निर्मित मूल्य के आधार पर लिया जा सकता है तथा यह 2603 अमरीकी डालर प्रति मी. टन बैठता है।

(II) जूलाई, 1995 में पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के समय प्राधिकारी द्वारा शुल्क की अनुशंसा करते हुए विचार किया गया सी आई एफ निर्यात मूल्य 1945 अमरीकी डालर प्रति मी. टन का था जिसमें निम्नानुसार अनवरत रूप से कमी हुई है;

अवधि	मूल्य (अमरीकी डालर)
अप्रैल—दिसम्बर, 1993	1945
जनवरी—मार्च, 1994	1938
अप्रैल— 1994	1732
जून—दिसम्बर, 1994	1727
जनवरी—1995, मार्च—1996	1747—1742
अप्रैल—सितम्बर, 1996	1607

(III) गणना के उसी आधार पर विचार करते हुए जिसे प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जांच में अपनाया गया था, जांच अवधि के लिए डंपिंग मार्जिन 1114 अमरीकी डालर प्रति मी. टन (39547 रुपए प्रति मी. टन) बैठता है। अतः डंपिंग मार्जिन 769 अमरीकी डालर से काफी अधिक बढ़कर 1114 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक पहुंच गया है।

(IV) निर्यात मूल्य में गिरावट के साथ-साथ आई बी बी पर सीमाशुल्क की 50% से कम होकर 42% (1995-96) हो गया है तथा इस समय यह 35% है, जिसके परिणामस्वरूप आयातकों के उताराई मूल्य में गिरावट आधी है और घरेलू उद्योग पर अत्यधिक मूल्य संबंधी दबाव पड़ा है।

(V) हालांकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के उन्हीं स्तरों को कायम रखा गया है, तथापि, घरेलू उत्पादकों को उचित लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा गया है। याचिकाकर्ता की मूल्य उगाही 117.18 रुपये प्रति कि. ग्रा. (1992-93) से घटकर 76.67 रु. प्रति कि. ग्रा. (जांच अवधि) हो गयी।

(VI) सरकार को 40080 रु. प्रति मी. टन का पाटन-रोधी शुल्क लगाना चाहिए, जो कि क्षति मार्जिन के बराबर है।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार :

3. चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों/निर्माताओं में से किसी ने भी प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है और न ही किसी टिप्पणी को प्रस्तुत किया है। आयातकों और/अथवा उपभोक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है :

(I) पूर्ववर्ती जांच में भी चीन में सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। लागत कीमत से कम पर बिक्री के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

(II) चीन जनवादी गणराज्य में लागत संबंधी आंकड़ों के अभाव में प्रतिनिधि देश के आधार पर लागत-निर्धारण किया जाना होता है। प्रतिनिधि देश के लागत आंकड़ों के प्रयोजन के लिए भारतीय निर्माताओं की लागत का चयन स्वयं यह विचार करते हुए वांछनीय नहीं होगा कि यह मामला भारत में आई बी बी के निर्माताओं से संबंधित है।

(III) सीमा-शुल्क में कमी किया जाना सार्वभौमिक तथ्य है और यह प्रोपिलीन और टोल्युइन (आई बी बी के निर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्रियां) समान रूप से लागू होती है।

(IV) आई बी बी पर पाटनरोधी शुल्क के मौजूदा स्तर ने भी आईब्युप्रोफिन उद्योग को आईब्युप्रोफिन की मौजूदा गिरती कीमत के साथ अव्यवहार्य बना दिया है। आईब्युप्रोफिन की डी पी सी ओ कीमत 521 रुपये प्रति किग्रा. (1994) से घटकर 442 रुपये (मौजूदा) प्रति किग्रा. तक कर दी गई है।

(V) भारतीय आईबीबी निर्माता अपनी क्षमताओं का विस्तार करते रहे हैं जिससे यह सिद्ध नहीं होता है कि निर्माताओं ने प्रतिकूल बाजारगत स्थितियों का सामना किया है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच :

4. याचिकाकर्ता, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गयी है, उन पर विचार किया गया है और जहां उपयुक्त समझा गया इसके बाद इस अधिसूचना में कार्रवाई की गई।

झ. विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग तथा समान वस्तुएं :

5. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तुओं से संबंधित पूर्व अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में कोई परिवर्तन नहीं है।

6. घरेलू उद्योग के संबंध में मैसर्स विनाती ऑर्गेनिकस लिमिटेड द्वारा याचिका दायर की गई है। प्राधिकारी ने आई बी बी के अन्य भारतीय निर्माता मैसर्स हर्दियालिया कैमिकल्स लि. (आगे इसे हर्दियालिया कहा गया है) को जांच शुरू किए जाने की सूचना दी। हालांकि, कंपनी ने 31 मई, 1997 तक समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, तथापि कंपनी से कोई सूचना/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। जांच अवधि के दौरान भारत में आई बी बी के कुल घरेलू निर्माण में विनाती ऑर्गेनिकस के निर्माण का एक बड़ा अनुपात रहा है और इस तरह विनाती ऑर्गेनिकस लि. घरेलू उद्योग की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। इसलिए विनाती ऑर्गेनिकस लि. पर वर्तमान समीक्षा के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में विचार किया गया है।

ख. पाटन :

7. प्राधिकारी ने धारा 9क(I) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं। लेकिन किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को कोई प्रत्युत्तर नहीं भेजा और न ही कोई सूचना भेजी। इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबंध देश के किसी भी निर्यातक ने नियमों के तहत उन्हें कोई सहयोग नहीं दिया है। प्राधिकारी का यह भी निष्कर्ष है कि चीन जनवादी गणराज्य में आई बी बी का सामान्य मूल्य स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन निर्यातकों/उत्पादकों की बनती है, जो प्राधिकारी को सहयोग देने में विफल रहे हैं।

8. इस दलील के संबंध में कि भारतीय निर्माताओं की लागत को प्रतिनिधि देश की लागत के रूप में नहीं माना जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि धारा 9क(I) ग(II) के अन्तर्गत सामान्य मूल्य मूल देश में निर्माण लागत का संदर्भ लेते हुए निर्धारित किया जाना होता है। यह दलील कि लागत प्रतिनिधि देश में निर्धारित की जानी चाहिए विधि-सम्मत नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में चीन जनवादी गणराज्य में निर्माण-लागत निर्धारित की थी। परन्तु, चीनी निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में आई बी बी की निर्माण लागत के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर निर्माण लागत निर्धारित की थी।

9. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए और रिकार्ड में प्रतिपक्षी सूचना दर्ज न होने के कारण प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के उसी स्तर पर विचार किया है जैसाकि पूर्ववर्ती जांच में विचार किया गया था।

10. याचिकाकर्ता ने अपनी निर्यात कीमत के दावे के समर्थन में भारत में आई बी बी के आयातों के सौदे-वार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। पूर्ववर्ती जांच में डीजीसीआईएण्डएस द्वारा समेकित सूचना के आधार पर निर्यात-कीमत निर्धारित की गई थी। परन्तु, यह पाया गया है कि आयात ब्यौरे, जो पूर्ववर्ती जांच

के समय डीजीसीआईएण्डएस द्वारा समेकित की गयी सूचना में आईबीबी के लिए अलग से उपलब्ध थे, जांच-अवधि के लिए उन्हें अन्य वस्तुओं के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए डीजीसीआईएण्डएस द्वारा समेकित सूचना से निर्यात-कीमत का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निर्यात-कीमत के दावे का किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा खण्डन भी नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर निर्यात-कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए कीमत-समायोजनों के उसी स्तर पर विचार किया है, जैसा कि पूर्ववर्ती जांच में किया गया था। इस प्रकार निकाली गयी निर्यात-कीमत को कारखानागत निर्यात-कीमत के रूप में माना गया है।

11. चूंकि, संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक और भारत के आयातकों ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने अलग-अलग निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन-मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को ध्यान में रखा है क्योंकि किसी अन्य पार्टी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजनार्थ पर्याप्त साक्ष्य के साथ कोई वास्तविक जानकारी प्रस्तुत नहीं की है और सामान्य मूल्य की भारत-औसत निर्यात-कीमत के साथ तुलना की है। यह तुलना निर्यात-कीमत के 74 प्रतिशत का पाटन-मार्जिन दर्शाती है।

ख. क्षति और कारणात्मक संबंध

12. इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनुपयुक्त होगा कि संबद्ध देश से किए गए आयात से घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मानदंडों की दृष्टि से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचेगी। घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कोई या सभी आर्थिक मानदंडों में सुधार के परिणामस्वरूप वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। परन्तु, यदि उत्पाद पाटित कीमतों पर जैसा कि मौजूदा मामले में है (बेचा जा रहा है और भारत में आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जो घरेलू उद्योग को उचित बिक्री कीमत से काफी कम हैं तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी। इसलिए घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मानदंडों के सुधार में पाटनरोधी-शुल्क समाप्त करने के लिए उचित कारण नहीं हैं।

13. घरेलू उद्योग को बिक्री वसूली में कमी को निर्माण लागत में कमी के संदर्भ में देखा जाना होता है। इसलिए बिक्री-वसूली में कमी से पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि की जरूरत पर विचार करने के लिए जो संबंधित कारक हैं, वे हैं पाटन-मार्जिन और क्षति की मात्रा (इसे क्षति-मार्जिन भी कहा गया है) हैं। तदनुसार, इन कारकों पर उत्पाद पर लगाया जाना जारी रहने के लिए अपेक्षित पाटनरोधी शुल्क के स्तर की सिफारिश करते हुए विचार किया गया है।

ग. पहुँच-मूल्य :

14. चीन जनवादी गणराज्य से हुए आयातों के पहुँच-मूल्य की गणना सीमा-शुल्क के प्रचलित स्तर और एक प्रतिशत उतराई और दो प्रतिशत हैंडलिंग-प्रभार जोड़ने के बाद निर्यात-कीमत से संबंधित पैरा 10 में उल्लिखित ब्यौरों के अनुसार भारत औसत निर्यात-कीमत पर विचार करते हुए की गई है। चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को पहुँच-मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है।

घ. अन्य मुद्दे

15. यह तर्क कि आई बी बी पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अंतिम उत्पाद अर्थात् आईब्युप्रोफिन की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है, वर्तमान समीक्षा पर निर्णय लेने और आई बी बी पर निरंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत के संबंध में असंगत है।

अंतिम निष्कर्ष

16. पूर्वोक्त बातों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि :—

- * चीन जनवादी गणराज्य मूल के या वहां से निर्यातित आई बी बी का भारत में निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है ;
- * यदि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी ;
- * यदि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

17. चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित आई बी बी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के लगाए जाने को जारी रखना उपयुक्त समझा जाता है।

18. इस बात पर विचार किया गया था कि क्या पहले जो शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकने में पर्याप्त होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों की भारत औसत पहुँच कीमत की तुलना जांच-अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से की गई थी। जहां कहीं यह अंतर डम्पिंग-मार्जिन से भी कमी है वहां डम्पिंग-मार्जिन से कम शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार यह सिफारिश की जाती है कि सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित आई बी बी के सभी आयातों पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 12465 रुपये (बारह हजार चार सौ पैंसठ रुपये) प्रति मी. टन की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

19. उपर्युक्त बातों के अध्याधीन 27 जुलाई, 1995 की अधिसूचना सं. 14/50/93-टी पीडी/एडीडी द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में कोई परिवर्तन नहीं है।

20. इस आदेश के विरुद्ध अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जाएगी।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 1998

Subject: Review of Anti-dumping duties concerning imports of Isobutyl Benzene - final findings

6/2/96/ADD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:
 - i. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) received a written request from M/s. Vinati Organics Ltd. under Rule 23 to review and increase the anti-dumping duty on imports of Isobutyl Benzene (referred to as IBB hereinafter) from the People's Republic of China (referred to as China PR or subject country hereinafter).
 - ii. The Authority issued a public notice vide Notification no. 6/2/96/ADD dated the 31st March, 1997, initiating review of definitive Anti Dumping Duty recommended on imports of IBB originating in or exported from China PR vide notification no. 14/50/93-TPD/ADD dated 27th July, 1995 and definitive Anti Dumping Duties imposed by the Central Government vide notification no 134/Customs dated 31st Aug., 1995.
 - iii. The investigations concluded by the Authority vide Notification no. 14/50/93-TPD/ADD dated 27th July, 1995 have been referred to as "the previous investigations".
 - iv. The Authority issued a public notice dated 31st March, 1997 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review of anti dumping duty concerning imports of IBB, classified under custom sub-heading 2933.40 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from China PR.
 - v. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters and industry associations (whose details were made available by the petitioners in the previous investigations) and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2).
 - vi. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumers of IBB in India (whose details were made available by

petitioners in the previous investigations) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter.

- vii. Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of IBB in India during the past three years, including the period of review. No information was however, received from CBEC
- viii. The Authority sent questionnaire to the known exporters, to elicit relevant information, in accordance with the rule 6(4). No exporter, however, filed response to the questionnaire.
- ix. The Embassy of China PR in New Delhi was informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers.
- x. A questionnaire was sent to the known importers and/or consumers of IBB in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4). No importer, however, filed response to the questionnaire.
- xi. Information relating to the extent of injury was called from the petitioner, which was also received. Information deemed necessary was verified by the Authority.
- xii. M/s. Herdillia Chemicals Ltd. (the other producer of IBB) was also informed about the initiation of investigations and requested to offer their comments, if any. Though the company requested for extension of time upto 31st May, 1997, no information/comment was received from the company.
- xiii. The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally before the Authority. The Authority held a hearing on 6th Oct., 1997, which was attended by the petitioner and M/s. Herdillia Chemicals Ltd. The parties attending the hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals, if any.
- xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file, maintained and kept open for inspection by an interested party.
- xv. In accordance with rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

- xvi. Investigation was carried for the period starting from 1st April, 1996 to 30th Sept., 1996.

B. VIEWS EXPRESSED BY THE PETITIONER

2. Vinati Organics Ltd. made the following submissions:

- i. The normal value for the purpose of these investigations can be taken on the basis of constructed value and the same comes to US \$ 2603 pmt.
- ii. At the time of imposition of anti-dumping duty in July 1995, the CIF export price considered by the Authority while recommending the duty was US \$ 1945 pmt, which has steadily eroded as follows:

<u>Period</u>	<u>Price (US \$ per mt)</u>
Apr.-Dec., 1993	1945
Jan.-March, 1994	1938
April, 1994	1732
June-Dec., 1994	1727
Jan., 1995 - March, 1996	1747-1742
Apr-Sept., 1996	1607

- iii. Considering the same basis of calculation as was adopted by the Authority in the previous investigations, the dumping margin for the investigation period comes to US \$ 1114 pmt (Rs. 39547 pmt). The dumping margin has, therefore, increased substantially from US \$ 769 to US \$ 1114 pmt.
- iv. Customs duty on IBB has also, alongwith decline in the export price, declined from 50% to 42% (1995-96) and is currently 35%, resulting in further decline in the landed value of imports and severe price pressure on the domestic industry.
- v. Even though the same levels of production have been maintained by the domestic industry, the domestic producers have been prevented from getting reasonable profits. Price realisation of the petitioner reduced from Rs. 117.18 per kg. (1992-93) to Rs. 76.67 per kg. (investigation period).
- vi. The Govt. should impose anti-dumping duty of Rs. 40080 pmt, which equivalent to the injury margin.

C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

3. None of the exporters/producers from China PR have responded to the Authority and offered any comment. The importers and/or consumers have expressed their views, and the same are briefly mentioned below:

- i) The normal value in China was not established even in the previous investigations. Drawing conclusions of sales below cost price is not sustainable.
- ii) In the absence of data relating to costs in China PR, cost determination on the basis of surrogate country has to be taken. Choosing cost of Indian producers for the purpose of surrogate country cost estimation itself will not be desirable considering that the matter pertains to the producers of IBB in India.
- iii) Reduction in the customs duty is universal and is equally applicable to Propylene and Toluene (the major raw materials for production of IBB).
- iv) Even the present level of anti-dumping duty on IBB has made Ibuprofen industry unviable with the current declining price of Ibuprofen. The DPCO price of Ibuprofen has been reduced from Rs. 521 per kg. (1994) to Rs. 442 (current) per kg.
- v) The Indian IBB producers have been expanding their capacities, which does not establish that the producers have suffered depressed market conditions.

D. EXAMINATION BY AUTHORITY

4. The submissions made by the petitioner, importers, consumers and other interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt hereinafter in this notification.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, DOMESTIC INDUSTRY AND LIKE ARTICLES

5. The final findings notified earlier with regard to the product under consideration and like articles remain unchanged.
6. With regard to domestic industry, the petition has been filed by M/s. Vinati Organics Ltd. The Authority informed the other Indian producer of IBB, M/s. Herdiallia Chemicals Ltd. (referred to as Herdiallia hereinafter), about the initiation of investigations. Though the company requested for extension of time upto 31st May, 1997 no information/comment was received from the company. Production of Vinati Organics account for a major proportion of the total domestic production of IBB in India during the investigation period and therefore, Vinati Organics Ltd. satisfies the definition of domestic industry. Vinati Organics has, therefore, been considered as the domestic industry for the purpose of the present review.

F. DUMPING

7. The Authority sent questionnaire to the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)c. However, none of the exporters responded to the Authority nor furnished any information. The Authority, therefore, holds that none of the exporters from

- the subject country have co-operated with the Authority as envisaged under the Rules. The Authority also holds that the primary responsibility to establish normal value of IBB in China PR rests with the exporters/ producers, who have failed to co-operate with the Authority.
8. With regard to the argument that cost of Indian producers cannot be treated as the costs in the surrogate country, the Authority notes that normal value under Section 9A(1)(c)(ii) has to be determined in accordance with reference to the cost of production in the country of origin. The argument that costs should be determined in the surrogate country is not supported by law. The Authority in the previous investigations determined cost of production in China PR. However, in view of non-co-operation from the Chinese exporters, the Authority had determined cost of production on the basis of the best information available with regard to the cost of production of IBB in China PR.
 9. In view of the foregoing and in view of non-co-operation from the exporters from China PR and no information on record to the contrary, the Authority has considered the same level of normal value as was considered in the previous investigations.
 10. The petitioner furnished transaction wise details of imports of IBB into India in support of its claim of export price. In the previous investigations, the export price was determined on the basis of information compiled by the DGCI&S. It is, however, found that the import details, which were separately available for IBB in the information compiled by DGCI&S at the time of previous investigations, are combined with other goods for the investigation period. It is, therefore, not feasible to determine export price from the information compiled by DGCI&S. Further, the export price claimed by the petitioner has also not been refuted by any interested party. The Authority has, therefore, determined export price on the basis of information furnished by the petitioner. The Authority has considered the same level of price adjustments as were carried in the previous investigations in view of non-co-operation from the exporters from China PR. The export price so arrived has been considered as ex-works export price.
 11. Since none of the exporters from the subject country and importers in India have responded to the Authority, the Authority has not determined separate dumping margins for individual exporters. The Authority has taken into account the information furnished by the petitioner, as no other party has furnished any factual information with sufficient evidence, for the purpose of fair comparison between the normal value and the export price and has compared the normal value with the weighted average export price. The comparison shows dumping margin of 74 percent of export price.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

12. It would be inappropriate to hold that the imports from the subject country would not cause injury to the domestic industry in the light of the economic parameters affecting the domestic industry. The improvement in any or all the

economic parameters affecting the domestic industry could be a result of the very fact of imposition of anti-dumping duties. The injury to the domestic industry would, however, recur in case the product is being sold at dumped prices (as the situation is in the instant case) and the imports are entering at such prices in India which is significantly lower than the fair selling price of the domestic industry. The improvement in the economic parameters affecting the domestic industry does not, therefore, warrant removal of anti-dumping duty.

13. The reduction in the sales realisation of the domestic industry has to be seen with reference to the reduction in the cost of production. Reduction in the sales realisation, per se, does not warrant a need for increase in the anti-dumping duty. The relevant factors for considering the need for increase in the anti-dumping duty are the dumping margin and the extent of injury (also referred to as injury margin). These factors have been accordingly considered while recommending the level of anti-dumping duty required to be continued on the product.

H. **LANDED VALUE:**

14. The landed value of imports from China PR has been calculated considering the weighted average export price as per the details discussed in para 10 relating to export price, after adding the prevailing level of customs duty and one percent landing and two percent handling charges. The anti dumping duty in force on imports from China PR has not been included in the landed values.

I. **OTHER ISSUES**

15. The argument that the imposition of anti-dumping duties on IBB has affected the price competitiveness of the end product, i.e., Ibuprofen is irrelevant to decide the present review and need for continued imposition of anti-dumping duty on IBB.

J. **FINAL FINDINGS**

16. The Authority concludes, after considering the foregoing, that:
- IBB originating in or exported from China PR has been exported to India below its normal value;
 - the domestic industry would suffer material injury in case the anti-dumping duty in force is removed;
 - the injury to the domestic industry would be caused from imports from China PR in case the anti-dumping in force is removed.
17. It is considered appropriate to continue the imposition of anti dumping duty on imports of IBB originating in or exported from China PR.

18. It was considered whether the duty recommended earlier would be sufficient to prevent the injury to the domestic industry. The weighted average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the fair selling price of the domestic industry determined for the period of investigation. Wherever the difference is lower than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly, it is recommended that anti dumping duty of Rs. 12465 (Rs. Twelve Thousand Four Hundred & Sixty Five only) per MT be imposed, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of IBB, falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from China PR.
19. Subject to above, the final findings notified vide notification no. 14/50/93-TPD/ADD dated 27th July, 1995 are unaltered.
20. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

